turers of food packets to print on these packs that the contents in the food packets are 100 per cent vegetarian; and

(b) if so, what steps have been taken by Government to implement this?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI RAM PUJAN PATEL): (a) No such representations have been received in the Union Ministry of Food and Civil Supplies.

(b) Does not arise. Moreover, printing of information on the food packet that its contents are 100 per cent vegetarian is outside the scope of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 and the corresponding Rules, namely, the Standards of Weights and Measures (Packaged Commodities) Rules framed thereunder.

राज्यों को खाद्य तेलों का आवंटन

2750. **श्री अजीत जोगी :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य तेल वर्ष 1988–89 और 1989–90 के वर्ष में आज की तारीख तक प्रत्येक राज्य को प्रतिमाह कितना–कितना खाद्य तेल आवंटित किया गया तथा उन्हें प्रतिमाह वास्तव में कितना-कितना खाद्य तेल उपलब्ध कराया गया ;

(ख) क्या प्रत्येक राज्य को आवंटित की गयी खाद्य तेलों की मात्रा उन्हें वास्तव में उपलब्ध करायी गयी थी ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और और क्या भविष्य में खाद्य तेलों की प्रतिमाह आवंटित मात्रा को उन्हें उपलब्ध कराया जायेगा ; और

(ग) राज्यों को खाद्य तेल किस किस आधार पर उपलब्ध कराया जा रहा है ; क्या इस संबंध में विभिन्न राज्यों के लिये भिन्न-भिन्न मान दण्ड अपनाये जाते हैं ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और क्या इस प्रयोजन के लिये समानता का व्यवहार किये जाने की संभावना है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) तेल वर्ष 1988–89 और 1989–90 के दौरान राज्यों को आवंटित की गयी आयातित खाद्य तेलों की मात्रा तथा उनके द्वारा उठाई गयी मात्रा दर्शाने वाले विवरण संलग्न हैं (देखिए परिशिष्ट 155, अनुपत्र सं. 94)।

(ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेलों की आवंटित मात्रा राज्य व्यापार निगम या हिन्दुस्तान वेजिटेबिल आयल्स कारपोरेशन एकक के प्राधिकृत डिपों से उठानी पड़ती है। जब कभी प्राधिकृत डिपो पर तेल उपलब्ध नहीं होता है, तब अन्तरिम उपाय के रूप में राज्य सरकारों से किसी अन्य डिपों से तेल उठाने का अनुरोध किया जाता है। पिछले कुछ महीनों के दौरान टिन–प्लेटों के उपलब्ध न होने, बन्दरगाहों पर खाद्य तेल के जहाजों के पहुंचान में देरी होने और तेल की ढुलाई के लिये "रेक" उपलब्ध न होने के कारण कुछ राज्यों के आवंटन में बाधा उत्पन्न हुई ऐसे मामलों में आवंटन उठाने के लिये समयावधि बढ़ाकर राज्यों को तेल उठाने के लिये अधिक समय दिया जाता है।

(ग) राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेल का आवंटन, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को उचित मांग, आयात के लिये प्राधिकृत मात्रा, खुले बाजार में देशीय खाद्य तेल के मूल्य, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तेल उठाने की गति तथा अन्य सम्बद्ध बातों को ध्यान में रखते हुए माह-दर-माह आधार पर किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आयातित खाद्य तेलों के आवंटन का उद्देश्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की समूची मांग को पूरा करना नहीं, बल्कि खुले बाजार में देशीय खाद्य तेलों की उपलब्धता की अनुपूर्ति करना होता है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का

आयातित खाद्य तेलों का आवंटन करने के लिये यह सिद्धांत समान रूप से अपनाया जाता है।

Augmentation of strength of Rural Labour Inspectors in Orissa

2751. SHRIMATI MIRA DAS: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the State Government of Orissa vide letter No. IIM/1-51/88/5289|LE dated the 26th May, 1988 requested the Central Government for the augmentation of the existing strength of the Rural Labour Inspectors for effective enforcement of the minimum wages in the agriculture sector;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) what is the decision, if any, taken by Government in this regard; and

(d) if answer to part (c) be in the negative, what are the reasons for delay in taking a decision in the matter and by when a decision is likely to be taken?

THE MINISTER OF LABOUR AND WELFARE (SHRI RAM VILAS PASWAN): (a) The letter No. IIM/1-51/88/5289/LE dated the 26th May, 1988 of the State Government of Orissa has not been received in the Ministry of Labour.

(b) to (d) Do not arise.

Amendment to workmen's compenesation Act

2752. SHRIMATI MIRA DAS: Will the Minister of LABOUR be peased to state:

(a) whether it is a fact that the State Government of Orissa in their letter No. 5444/LEIVW(b)2-46/88 dated 12th May, 1988 proposed to amend sec. 21 of the workmen's compensation Act in regard to the transfer of claim cases of migrant workers to the compensation commissioners of their respective States and also for enhancement of penalty under Inter-State Migrant Workmen's Act, 1979;

(b) whether it is also a fact that a joint study team set up by Government had made certain recommendations to amend sec. 21(2) of the workmen's compensation Act 1923; and

(c) if so, what is the decision, if any, taken by Government in the matter stating the reasons for delay in bringing a legislation to this effect?

THE MINISTER OF LABOUR AND WELFARE (SHRI RAM VILAS PASWAN): (a) and (b) Yes Sir.

(c) The suggestion for amendment of section 21 of the Workmen's Compensation Act, 1923 is included in the current batch of proposals for amendment of the Act, which is separately under consideration. The suggestion for enhancement of penalties under Inter-State Migrant Workmen Act, 1979 is not being processed for the present, pending receipt of the Report of the National Commission on Rural Labour, which has set up a Study Group on Migrant Labour. The delay in bringing forward a legislation for amendment of the WC Act is mainly due to the fact that there are large number of proposals for amendment of the Act, which have to be finalised in consultation with he Organisations of Employers/Employees and the State Governments.

Central Training Organisation in Orissa

2753. SHRIMATI MIRA DAS: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether any proposal is under Government's consideration for setting up of a Central Training Organisation in Orissa for training the management and workers in handling major industrial hazard situations in the State;